कैश कार्ड योजना के मामले में कार्ड धारक तब तक खोये या चोरी गये कार्ड के बदले की गई खरीद के लिये उत्तरदायी होगा जब तक कि बैंक को लिखित रूप में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हो जाती है।

(ग) क्रेडिट कार्ड योजनाओं में एकरूपता लाने के लिये मार्गनिर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए निवेश संबंधी दिशा-निर्देश

830. **श्री अजीत जोगी:**
चौधरी हरि सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक्रों द्वारा किए जाने वाले निवेश संबंधी अपनी वर्तमान नीति पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) से (ग) जुलाई 1991 में सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति में, निजी निवेश को बढ़ाने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदम शामिल हैं। इस समय, औद्योगिक लाइसेंसिंग पद्धति केवल 15 मदों को छोड़कर सभी के लिए समाप्त कर दी गई हैं, सरकारी क्षेत्र के लिए प्रारक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 6 कर दी गई है; और सरकारी क्षेत्र निवेश के लिए चुने गए कुछ चयनित आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र सहभागिता को भी अनुमति दी गई है। विदेशी निजी निवेश के लिए नीति को विभिन्न उद्योगों में 51 प्रतिशत इक्विटी तक विदेशी निवेश तथा मानकों और कार्य प्रणालियों की छूट के लिए स्वतः अनुमोदन के प्रावधान सहित पर्याप्त रूप से उदार बनाया गया है।

Mint Deal Awarded to Japanese firm

831. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item captioned 'Mint deal for Japanese firm questioned, reported in the Statesman dated the 21st December, 1993;

(b) if so, whether members of the Governing board of the Reserve Bank of India have seriously protested against the decision to award the contract to a Japanese firm;

(c) whether Government propose to probe the rule of reserve Bank of India through CBI/investigating agency; and

(d) if so, the details thereof;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED):(a) Yes, sir.

(b) The matter was discussed by the Board of RBI on several occasions and the views of the various Members were taken into account.

(c) and (d) As no violation of prescribed procedure has been reported, holding of any probe into the role of RBI in this case does not arise.

Real Estate Purchases by Income Tax Department

832. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Income Tax Department purchases real estate where it feels that it is under priced;

(b) details of this policy;

(c) details of amount involved which require or come within the purview of this policy; and

(d) the changes proposed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) The Question relates to Chapter